firm except in cases like those which Shri Abid AH has pointed out.

SHRI M. P. BHARGAVA: Sir, I have just a small submission to make before you pass on to the next subject, and it is that the Government be directed to circulate copies to all the Members of Parliament as early as possible, because my own information is that a very limited number of copies have come and they will not be sufficient for all the Members who are interested in taking part in the discussion.

श्री राजनारायण : इतनी तेज रफ्तार से दुनिया चल रही है कि कौन मरने के लिए रहेगा पांच दिन के बाद और कौन नहीं रहेगा। बेकार की बात कर रहे हैं ।

MR. CHAIRMAN: I will request you to see that a sufficient number of copies are made and distributed to all the Members at the earliest possible time.

SHRI M. C. CHAGLA: That will be done as soon as possible.

THE LAND ACQUISITION (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 1967—*contd.*

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर था, वह प्वाइंट आफ आर्डर सुझावात्मक था लेकिन उस समय चेयर पर श्रीमान भार्गव साहब बैठे हुये थे, सदन स्थगित करके उन्होंने कहा कि दूसरे दिन उठाना ।

हमारे यहां लैंड एक्विजिशन विधेयक है, उस पर चर्चा चल रही है, उसमें जो दो कमियां हैं उनको मंत्री जी से डिसकस किया बोलने के बाद, मंत्री जी ने एक डिफिकल्टी हमको बताई, वह हमारी बात से सहमत हैं और कहते हैं कि मगर डिफिकल्टी यह है...

श्री सभापति : इसके माने यह है कि आप इस मामले पर दुबारा कह रहे हैं, पहले तो आप कह चुके हैं ।

श्री राजनारायण : कहने ही नहीं दिया, सदन उठ गया । जो डिफिकल्टी मंत्री जी ने बताई उस डिफिकल्टी का रास्ता बता रहा हूं । रास्ता यह है । यह सही है कि 18 मार्च को दोनों सदन बैठे और दोनों सदन के बैठने के छः हफ्ते बाद तक वह आर्डिनेंस फोर्स में रहता है और अभी छः हफ्ते हुये नहीं हैं तो उसका साल्यूशन रास्ता यह हो सकता है कि सदन प्रोरोग नहीं हो । संसदीय प्रथा में यह है । हमारे कौल साहब यहां नहीं दिख रहे हैं, इन्होंने भी हमारे साथ थोड़ी मेहनत की, लेकिन हमारे यहां विधान सभा में बराबर होता कि हाउस एडजार्न होता है और प्रोरोग होता है, दो शब्दों का इस्तेमाल होता है तो जब एडजार्न होगा तो यही माना जायगा कि हाउस इज इन सेशन और जब प्रोरोग हो जायेगा तो मतलब होगा कि हाउस सेशन में नहीं है । मेरा अर्थ यह है कि अगर हाउस आज या कल या परसों प्रोरोग न हो और आप इस हाउस को एडजार्न करें और लोक सभा के जो स्पीकर साहब हैं वह भी उसको एडजार्न करें और बीच में 15 दिन के बाद सेशन को बुला लिया जाय तो मंत्री जी की डिफिकल्टी रिमूव हो जाती है । गड़बड़ यह है कि, श्रीमन्, जैसे हमारी 10 एकड़ जमीन है, सरकार ने ले लिया, दो एकड़ जमीन पर सरकार ने अपना इम्प्रूवमेंट किया और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया 11 महीने पहले उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो 8 एकड़ जमीन हमारी बची थी उसके हम मालिक हो गये और 8 एकड़ में हमने कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिया लेकिन अगर यह विधेयक जैसा आया है कानून की शक्ल में आ जायगा तो बिना एक पैसा मुआविजा दिये ही सरकार हमारी सारी इम्प्रूवमेंट की हुई जमीन को ले सकेगी, इसलिए इसमें बड़ी खराबी है । मंत्री जी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि हाउस की एक कमेटी बनावें और यह कमेटी तमाम डिफिकल्टीज को देखे और आगे फिर विधेयक लायेंगे तो आगे विधेयक लाने की

[श्री राजनारायण]

करते नहीं अगर हमारा सजेशन मान लें, सेलेक्ट कमेटी को बिठाने का प्रस्ताव कबूल करें, हाउस एडजार्न किया जाये, प्रोरोग न किया जाय एडजार्न होने से जो छः हफ्ते वाली शर्त है वह अपने आप पूरी हो जायगी।

श्री सभापति : यह प्वाइंट आफ आर्डर था।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, सुझावात्मक प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री सभापति : मैंने अपनी वाकफियत के लिए पूछा।

श्री राजनारायण : सुझाव मैंने दे दिया, प्वाइंट आफ आर्डर कहिये, प्वाइंट आफ क्लैरिफिकेशन कहिए या कुछ भी कहिये।

MR. CHAIRMAN: Mr. Chordia was speaking on the last day. You may begin now, Mr. Chordia. The House will sit through lunch.

SHRI P. K. KUMARAN (Andhra Pradesh): We are sitting tomorrow also. Why through lunch, Sir?

SHRI LOKANATH MISBA (Orissa): If we are sitting tomorrow, I think we may have the usual lunch interval, Sir.

MR. CHAIRMAN: There is ample bywork, as you will see.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चोरड़िया (मध्य प्रदेश) : सभापतिजी, लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट बिल के बारे में जो चर्चा चल रही थी उसमें मैंने निवेदन किया था कि हमारे यहां पर जो भूमि का अधिग्रहण होता है उसमें हमारी सरकार बड़ी उपेक्षा की प्रवृत्ति का परिचय देती है और इसीलिये मध्य प्रदेश में भी जब दुर्ग जिले में भिलाई के कारखाने के लिये भूमि का अधिग्रहण किया गया तो हमारी सरकार ने पहले धारा 4 (1) के अन्तर्गत एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और फिर तसल्ली के साथ इत्मीनान के साथ, जैसे जैसे जिस-जिस अफसर की जो जो विम्स हुई और उन्होंने समझा कि यह काम अपने को करना पड़ेगा उसी के अनुसार उसके लिये धारा 6 के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उनको प्राप्त करने का प्रयास किया।

सभापति जी, हमारे यहां जो मूल विधान है उसमें शब्द "एरिपोर्ट" का आता है, धारा 5 ए, उपधारा 2 में जब एक रिपोर्ट का उल्लेख आता है तो यह अत्यंत आवश्यक है कि धारा 4 (1) के अन्तर्गत जितने क्षेत्र के लिए नोटिफिकेशन होते हैं उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार कर के हमारे कलेक्टर सहाब दे और उसको प्राप्त करने के बाद ही धारा 6 के अंतर्गत हमारी सरकार उसका नोटिफिकेशन करे। इसके बाद भिन्न भिन्न न्यायालयों का भिन्न भिन्न मत रहा और उसके परिणामस्वरुप मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, मध्य प्रदेश के श्री विष्णु-प्रसाद शर्मा जो दुर्ग के थे वह सुप्रीम कोर्ट तक गये आखीर में इस प्रश्न को तय करवा सके कि जो नोटिफिकशन धारा 4(1) के अन्तर्गत हो जाता है उसकी जो अलग अलग हिस्से में तसल्ली के साथ हमारी सरकार धारा 6 की नोटिफिकेशन किया करती है वह उचित नहीं है, न्यायसंगत नहीं है और हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपील की थी उसको उसने कास्ट के साथ खारिज किया। सभापति जी, यह विष्णु प्रसाद जी ने हमारी सरकार की आंखे खोली, उनको कानून की एक सही बात को सरकार से मनवाने के लिये कितनी तकलीफ उठानी पड़ी होगी उसकी अनुभूति न कर के उन्होंने जो कष्ट उठाया, जो खर्च किया, जो मेहनत की, सब कुछ को हमारी सरकार इस आर्डिनेन्स के द्वारा, जिसको अब कानून की शक्ल देने जा रही है, मिट्टी में मिला देना चाहती है, यह कभी भी न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।

सभापति जी, कानून के अन्तर्गत किसी को एक अधिकार दिया है, उसका दुरुपयोग होता है और फिर वह उच्चतम न्यायालय से निर्णय करवा लेता है कि इसको अधिकार था किन्तु फिर कलम की एक नोक से उसको ले लेना और उसकी सारी मेहनत, उसने हजारों रुपया जो खर्च किया, जो ज्ञान आपको दिया उसका परिणाम, उसका इनाम यह देना चाहते हैं कि तेरी सारी आजतक की मेहनत को इस आर्डिनेंस के द्वारा, इस कानून के द्वारा, खत्म कर देते हैं यह कुछ उचित नहीं। मगर हमारे मंत्री जी कहते हैं कि उस जगह कारखाना बना लिया, बिल्डिंग्स बना ली। मैं भी इस मत का नहीं हूं कि उसको तोड़ कर उसका कब्जा दिला दे मगर यह जरूर चाहूंगा कि जिस आदमी ने ज्ञान दिया, जिस आदमी ने कानून का अधिकार प्राप्त करने के लिये बहुत खर्च किया और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कास्ट दिलाई उसकी अनुभूति करें, कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कास्ट दिला दी लेकिन हम और आप सब जानते हैं कि अगर एक लाख रुपया खर्च होता है तो जो कास्ट का केलकुलेशन होता है वह 25 हजार का ही होता है और और ऐसी स्थिति में अपनी गिरह से 75 हजार रुपया लगाना पड़ता है।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): May I submit, Sir, that this Ordinance does not apply only in an individual or particular case? It covers a large number of cases where projects are likely to be affected. And this Act has been in force for the last about 75 years. So the Ordinance has not been promulgated in order to meet the requirements of a particular case as such.

श्री राजनारायण : उसमें इनडिविजुअल भी तो आता है।

श्री वि[illegible] मन्नालालजी चौरड़िया : सभापति जी, [illegible] ऐसा निवेदन कर चुका हूं कि दोनों तरह के मत थे, पंजाब हाई कोर्ट ने दूसरी रूलिंग दी और सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी रूलिंग दी, पंजाब हाई कोर्ट की रूलिंग चल रही थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद यह चीज पैदा हुई और अगर ऐसा किसी की वजह से हुआ तो श्री विष्णु प्रसाद की वजह से हुआ। तो श्रीमन्, विष्णु प्रसाद ने जितनी मेहनत की वह काहे के लिये की, उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन हुआ था वह गलत है और इसलिये इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही की वह गलत है, तो उनको यह अधिकार प्राप्त हो जाता था कि जिस भूमि के लिये, जिस क्षेत्र के लिये गलत कार्यवाही की वह उनके कब्जे में रहे, वह उनका उपयोग करें अगर एक्वायर करते तो नया नोटिफिकेशन जारी कर के आज की डेट से करते, यह सारी बात सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद तय हुई। तो उसने आपको ज्ञान दिया और यह मानना पड़ेगा कि उसने हमारी सरकार की आखें खोली, हमारी सरकार को बताया कि यह कानून जो 1894 ई० में बनाया था उसका असली मंशा यह है। इस बात का ज्ञान देने वाले को उसका इनाम देने की अपेक्षा कि जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से प्राप्त हो गया वह रहे उसको आप सजा देना चाहते हैं। इसलिये स्थिति यह है कि चाहे जितनी मेहनत कर ले लेकिन हमारे पास वह ताकत है, हमारे पास बहुमत का ऐसा जोर है कि जिसके आधार पर हम इस प्रकार का कानून बना कर तेरी सारी मेहनत, सारे प्रयत्न, और सारे खर्च को असफल बना सकते हैं, वही हमारी सरकार कर रही है।

SHRI ANNASAHIB SHINDE: I think the hon. Member is misunderstanding.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : सभापति जी, अब जहां तक इस संशोधन का सवाल है इसका प्रभाव दिल्ली पर बहुत व्यापक रू[illegible]

[श्री विमल कुमार मन्नालालजी चौरड़िया]

है । हमारा जो पुराना कानून था उसके अनुसार हमारी दिल्ली स्थित सरकार और दिल्ली डेवेलपमेंट अथरिटी ने लैंड एक्विजिशन एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत 1959 में 34,000 एकड़ और 1961 में 16,000 एकड़ जमीन के लिये अक्वायर होने का नोटिफिकेशन जारी किया, इस प्रकार 50,00 एकड़ जमीन लेने की उन्होंने घोषणा कर दी कि हमको इतनी जमीन की जरूरत लगेगी । उसमें विज्ञप्ति के बाद अब तक न कोई आदमी कुंवा खोद सकता है, न मकान बना सकता और अगर मकान भी बनवा लिया, कुंवा भी खोद लिया, तो सरकार उसको उसका कम्पेन्सेशन देने वाली नहीं है क्योंकि जसके लिये भी कम्पेसेशन दिये जाने वाले भूमि के क्षेत्र की 1959 में विज्ञप्ति कर दी गई है । अगर कोई खेत वाला जमीन वाल गरीब आदमी है, उसकी जमीन आप लेते हैं लेकिन उसको अभी तक कम्पेन्सेशन देते नहीं जमीन छोड़ते नहीं और उस कुछ करने नहीं देते, इस तरह से बड़े धर्मसंकट की स्थिति में यह सरकार उनको रखती है। अथारिटी ने इस तरह से धारा 6 (1) के अंतर्गत 12 जून 1961 को 100 एकड़, 14 जून 1961 को 220 एकड़, 16 मई, 1962 को 200 एकड़, 1963 में 4,500 एकड़, 25-1-65 को 8,000 एकड़ और 1966 में 15000 एकड़ के करीब जमीन के लिये नोटिफाई किया कि यह जमीन सरकार लेना चाहती है । असल बात यह होनी चाहिये थी कि जितना काम करने की आपकी ताकत थी, क्षमता थी, उतना ही आप अपने हाथ में लेते मगर योजनाएं तो आपकी बड़ी बड़ी होती हैं पर पैसा जेब में होता नहीं है । मकान और भवन बनाने की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं कुछ कर नहीं पाते लोगों को रहने के लिये मकान मिलता नहीं । सरकार ऐसी नीति का निर्धारण करना चाहती है कि लोग मकान बनाना भी चाहते हैं तो उनको बनाने नहीं देती, जमीन बेकार पड़ी रहती है तो पड़ी रहे उसको कोई चिन्ता नहीं । यह वैसा ही किस्सा हुआ जैसे एक गाय कहीं भूसा खा रही है और उस भूसे की जगह एक कुत्ता बैठकर भूकें , अंग्रेजी में उसको "डाग इन द मैंगर पालिसी" कहा जाता है ।

SHRI ANNASAHIB SHINDE: I think the hon. Member's party members are now associated with the Delhi Administration and if according to him there is injustice, I think justice should be possible now.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : सभापति जी, अगर वह भी गलती करें तो उनकी भी अलोचना करने का मुझको अधिकार है । आज वह स्थिति है नहीं जिस तरह की हरकत आप कर रहे हैं अगर वे भी करते रहेंगे तो मैं उनकी बराबर आलोचना करने वाला हूं, पीछे हटने वाला नहीं ।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि उस अधिग्रहण की जमीन में उत्तर प्रदेश हाउसिंग सोसायटी तथा सैनिक हाउसिंग सोसाइटी की भी भूमि है जो कि सरकार उन्ही से लेकर दूसरी सोसायटीज को देने जा रही है । अगर एक सोसाइटी से छीन कर दूसरी सोसाइटीज को दे दी जाय जब कि पहली वाली सोसाइटी ने डेढ़ रु० और 3 रु० प्रति वर्ग गज भाव से किसी से खरीदी हो और हमारी सरकार जो कम्पेन्सेशन देने वाली है है वह 50 पैसा , 60 पैसा 80 पैसा के हिसाब से पर स्क्वायर यार्ड के लिये देने वाली है । हमारी सरकार ने जो कुल 28,000 एकड़ जमीन धारा 6 के अंतर्गत एक्वायर करली उसमें से केवल 5000 एकड़ विकसित की, क्योंकि नोटिफ़िकेशन तो 50,000 एकड़ के लिये निकला था और 1960–61 में आब्जेक्शन सुनने के बाद वह जमीन लगभग 28 हजार एकड़ रह गई थी जिसमें से केवल 5,000 एकड़ अभी तक उन्होंने विकसित किया । इस पर सरकार उनके अब दाम

देगी पुराने 1959 व 1961 के भाव से तो सभापति जी, यह तो कोई न्यायोचित काम हुआ नहीं । हमारी सरकार खरीद रही है 50 पैसा, 60 पैसा और 80 पैसा प्रति वर्ग गज के भाव से जब कि सोसाइटीज ने खरीदा डेढ़ रु० दो रु० के हिसाब से ।

वितरण के लिए भी दो तरह की जमीनें हैं, एक तो अन्डेवलप्ड और एक डेवलप्ड जहां तक अनडेवलप्ड जमीन का सवाल है सभापति जी, हमारी सरकार ने जो 60, 70 पैसे के भाव से खरीदा था वह सहकारी समितियों को भी 8 रु० प्रति स्क्वायर यार्ड के हिसाब से देने वाली है । अभी उसमें एक शर्त यह जोड़ी गई है जब कि एक इन्सटालमेंट जमा भी हो चुका है कि इस तरह से जो जमीन सोसायटी को मिलेगी उसी में वह मकान बनाने के लिये जो प्लाट बनायेगें उनके अंतर्गत ही स्कूल के लिये, सार्वजनिक स्थानों के लिये जगह छोड़ने के बाद लोगों को वह प्लाट दिये जायेंगे उसमें उनकी वह मेहनत भी शामिल है जो तिकड़म लगाकर जमीन प्राप्त करने में अगवा बन जाते हैं । तो जो 60, 70 या 80 पैसा प्रति स्क्वायर यार्ड के हिसाब से जमीन सरकार ने खरीदी वह मकान बनाने वालों को 18 या 20 रु० प्रति स्क्वायर यार्ड पड़ने वाली है । तो यह हमारी सरकार के लिये जो कि हर बात पर सोशल वेलफेयर स्टेट का नारा लगाती है और खुद इस तरह से पैसा अर्जित करती है उचित नहीं कहा जा सकता ।

सभापति जी इसी तरह से कि धारा 10-11 के अंतर्गत अवार्ड देना चाहिये, अवार्ड देकर धारा 10 के अंतर्गत शासन में कब्जा लेना चाहिये और ऐसा बहुत बड़ा हिस्सा है जो सरकार ने अभी तक अपने कब्जे में लिया नहीं और उसकी विज्ञप्ति कर रखी है । इस अनडेवलप्ड जमीन को लेकर बहुत से लोगों ने अपना रुपया रिस्क कर रखा है । इसमें एक नया क्लास नयी जमात कालोनाइजर्स की खड़ी हो गई है । दुनिया में परेशान होने वालों की कमी नहीं है और उनकी परेशानियों का नाजायज लाभ उठाने वालों की कमी नहीं है । इसलिये कालोनाइजर्स आगे आये । कालोनाईजर्स ने जमीन वालों से मिल कर भूमि वालों से मिल कर वह जमीन खरीदी और जमीन उन्होंने रुपया, दो रुपयों या तीन रुपयों के भाव खरीद कर 3, 4 रुपये सेलेकर 10, 15 रु० प्रति गज के हिसाब से जो मकान बनाने वाले थे उनकों बेच दिया । अब कालोनाइजर की जो जमात थी, वह बीच में से हट जाती है । अब सरकार सीधे उन लोगों से जिन्होने मकान बना लिये इस भूमि पर जो अन्डेवलप्ड है, और लगभग एक लाख मकान ऐसी भूमि पर जिस पर धारा 6 की विज्ञप्ति हो चुकी है बने हुए हैं, वह हिस्सा अक्वायर करने वाला है । अब तक इस प्रकार की भूमि पर लगभग 1 लाख मकान बन चुके हैं । यदि एक लाख मकानों के हिसाब से जोड़ा जाय तो एक एक मकान की एवरेज कीमत 7,000 बैठेगी, कम से कम 3,000 के हिसाब से और ज्यादा से ज्यादा 15,000 के हिसाब से , और इस तरह से 70 करोड़ रु० की लागत की जायदाद वहां पर तैयार हो चुकी है, उसमें पांच लाख लोग रहते हैं । अभी तक तो जब तक कि कानून नहीं बना था उनको अधिकार था सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के केस को खत्म करवा कर अपना कब्जा करवा सकते थे मगर इस कानून के बन जाने के बाद दिल्ली के वह निवासी जो एक लाख के करीब मकान बना चुके हैं जो 70 करोड़ रु० की प्रापर्टी उनकी बन चुकी है, उसको यह सरकार छीन सकती है क्योंकि कानूनन उसको अधिकार दिया जा रहा है, और मुआवजा दिया जायेगा 70 करोड़ की जायदाद का 1 करोड़ रु० के करीब । तो मैं प्रार्थना करूंगा कि यह इस तरह की सोशल वैलफेयर स्टेट बनी है । आप जो कहते

[श्री विमल कुमार मन्नालालजी चौरड़िया]

हैं मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान है तो यह गरीब लोगों के लिये प्लान नहीं है । मास्टर प्लान को अगर चलाना है तो लोगों को कष्ट में डाल कर आप मास्टर प्लान चला नहीं सकते । अगर मास्टर प्लान सफल बनना है तो लोगों की सुविधा का आप ध्यान रखें ।

MR. CHAIRMAN: Mr. Chordia, if I may interrupt you, you have taken fifteen minutes last time and you are now taking considerable time. Won't you like to wind up now?

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : पांच मिनट और । सभापति जी, इसी तरह से जो डेवलप्ड प्लाट्स हैं उनको हमारी सरकार की तो दिल्ली डेवलपमेंट अथारिटी है उसने 70 पैसे के भाव से जमीन खरीदी और औसतन 6 से 8 रु० खर्च करके उसके डेवलपमेंट पर लगाये और फिर भी जमीन प्लाट बनाकर तीस पैंतीस रु० प्रति स्कवायर यार्ड के भाव से जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनको मकान बनाने के लिये दी और दूसरों को 100 से लेकर 150 रु० के भाव से दिया और जो व्यापार के क्षेत्र हैं, जैसे दुकानों के लिये या सिनेमा घर के लिये, वहां 200 से 500 रु० प्रति स्क्वायर यार्ड के हिसाब से जमीन बेची है । यह एक सोशल वेलफेयर स्टेट के लिये कोई शोभा की बात नहीं कही जा सकती और न्याय की बात भी नहीं है ।

सभापति जी, हमारी सरकार लोगों के साथ विश्वासघात भी कर रही है । दिल्ली डेवलपमेंट अथारिटी ने क्या किया कि उन्होंने कहा लोगों से कि तुम्हारी जो जमीन लगे उसके बदले में आल्टरनेटिव प्लाट्स देंगे लेकिन आज तक धारा 16 के अंतर्गत उनको कम्पेन्सेशन का पैसा नहीं दिया और जब तक पैसा नहीं देते तब तक उनके पास यह अधिकार नहीं कि आल्टरनेटिव प्लाट ले सकें । बिना जमीन के वे मकान नहीं बना सकते हैं । तो नोटीफिकेशन तो कर दिया है आल्टरनेटिव प्लाट देने का लेकिन इस तरह से बीच अधर में उनको लटका रखा है । जो मकान बनवाना चाहता है या तो आप उनकी जमीन लेकर मकान बनवा दीजिए, और अगर आप इसमें असमर्थ हैं तो आप उनको बनवाने दीजिए । लेकिन उसको अपने अधिकार से वंचित करना उचित नहीं है ।

जहां तक सुझाव और मांग का सवाल है, मैं निवेदन करूंगा कि सब से पहले आप मेहरबानी कर के इस बिल को वापस ले लीजिये जिससे ये जो परेशानियां बढ़ने वाली हैं, ये न बढ़ें । मगर यदि आप को ऐसा लगता है कि अगर यह बिल हमने वापस लिया तो हमारे स्टील के प्लांट में सारी कठिनाई आ जायेगी, तो दूसरा आल्टरनेटिव यह है कि जो जमीन सरकार ने अभी तक अपने कबजे में ले ली है, जिस पर मकान, बिल्डिंग्स वगैरह बना लिये हैं उसको छोड़ कर बाकी पर यह कानून लागू नहीं होना चाहिये, ऐसी व्यवस्था करने का कष्ट करें ।

तीसरे दिल्ली में 1959 से धारा 4 के अन्तर्गत नोटिस जारी करके जिस भूमि पर कबजा सरकार ने लिया है, केवल उसी को रखे और बाकी को छोड़ दे और अगर आपको फिर नोटिफाई करना है तो नोटिफाई करके आज की तारीख से कम्पेंसेशन देने का कष्ट करे, न कि 1959 में जो नोटिफिकेशन दिया था, उसी के अंतर्गत आज भी देते रहें । इसके साथ साथ सरकार द्वारा जो नफाखोरी की जा रही है, चाहे वह दिल्ली डेवलपमेंट अथारिटी के नाम पर हो या किसी के नाम पर हो, उससे जनता पिस रही है और हम को जनता से मतलब है । इसलिये वह जो नफाखोरी चल रही है कि 70,80 पैसे स्क्वायर यार्ड के 500 रु० ले लेते हैं, यह उचित नहीं है और इसको बन्द करना चाहिये । कृषि योग्य भूमि कभी भी इसमें

लेने का प्रयत्न नहीं करें । अपवादस्वरूप जब अति आवश्यक हो तभी लेने का कष्ट करें । आशा है कि मंत्री महोदय इन सुझावों पर ध्यान देंगे और उचित कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे । मैंने अमेंडमेंट भी दिये हैं और मैं अपने अमेंडमेंटस पर भी चर्चा करूंगा । धन्यवाद ।

SHRI N. PATRA (Orissa): Mr. Chairman, Sir, I rise to support this welfare measure but while supporting it I want to point out the way the acquisition proceedings are being V»ken in my State erf Orissa.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) in the Chair.]

Laxge acreage of land for the Maha-nadi and the Delta Irrigation Projects wa_s acquired and it is a long time since that was done but compensation due to the people who were deprived of their valuable land has not been paid as yet and payment of lakhs of rupees is still pending. From my own personal experience I can give another instance where a plot of land was acquired some 7 or 8 years back for the construction of a police station. That was a village site meant for house building purposes and those people who were owners of the land were small holders. They had even dug foundations for building their houses but this piece of land was acquired for building a police station and these people who have been deprived of their land have not been paid the proper compensation. This is from mv personal experience. The poorer sections of the people who are deprived of their holdings, of their valuable property, are not being paid properly and in time. The previous speaker from the benches opposite, Mr Chordia, lucidly explained how people are being harassed in the matter of payment of proper compensation. Therefore, I would suggest to the Government that when they think of taking over the land for development purposes, as soon as the notification is made ready they should start clearing the dues in time. Further they should not expect a small person who is deprived of his valuable land to run to the kutcheri several times to receive the compensation. I know the people who were deprived of their house sites at my place had to wait long for getting compansation and they naturally had to *go* to same other place for eking out their livelihood, that is, to Calcutta. But for receiving this small amount as compensation for their land they had personally to come down to the local Treasury in Orissa. Those harass-ments and indignities have to be kept in view and the Government should see that proper compensation is paid in time.

Recently in Madras one Mr. Vajra-velu in Madras filed a suit for his compensation and the Supreme Court has decreed in his favour saying that the payment of compensation was not being properly made to him. Before the Fourth Amendment of the Constitution a person who was being deprived of his land used to get even the potential value of the land.

SHRI SUNDAR MANI PATEL (Orissa): Fourth Amendment of the Constitution.

SHRI N. PATRA: Yes. The potential value was to be paid but after the Fourth Amendment he would get just equivalent valuo, that is, the market value. Then we had another amendment, the Seventeenth Amendment,, whereby the position of the tenant has been ameliorated to a smalt extent; that is, it has been made obligatory on the part of the acquiring authorities to pay him market value.

SHRI SUNDAR MANI PATEL: S» my friend does not agree with trie Seventeenth Amendment?

SHRI N. PATRA: Whether you agree or not, it is a separate question. What I have said is that the position of the person who is deprived of his land has been further ameliorated by the Seventeenth Amendment when compared to the position that obtained as a result of the Fourth Amendment. So there is no question of agreeing or disagreeing. I am now stating in a nutshell the comparative positions before and afte$_r$ th$_e$ Fourth Amendment. Briefly the position before the Fourth Amendment of 1955 was—

(1) The law had to provide for the payment of just equivalent of the property acquired;

(2) The expression 'just equivalent' was taken to mean not only the market value of the property at the time of acquisition but also its potential value;

(3) If either of these values were omitted, then the resultant amount of compensation was not a 'just equivalent' of the property acquired and the court could set aside the law on the ground of inadequacy of compensation.

In Vajravelu's case the Supreme Court had to intervene and set it right. Now the position after the Constitution (Fourth Amendment) Act, 1955 is: —

(1) The law has to provide for the payment of 'just equivalent' of the property acquired;

(2) If the principles laid down by law ^0 not take into account the value of the property at or about the time of acquisition, the law will be struck down on the ground °^{x} violation of article 31(2);

(3) The non-consideration of the potential value of the property is perhaps no ground for strik ing down the law as it pertains to the domain of adequacy of compensation;

(4) If the principles do not take into consideration the value of the property at or about the time of acquisition the law is liable to be set aside a$_s$ it pertains to the domain of the principles of compensation which is within the jurisdiction of the courts.

But I may say in this context that the large social and economic goals set out in the Constitution in the Preamble and Chapter IV cannot be achieved if we see to the dictionary meaning of the word 'compensation'. Therefore whatever the Supreme Court may observe, a flexible meaning has to be taken otherwise the various welfare measures and other development projects cannot be properly carried out.

With these observations I resume my seat

12 NOON

श्री शीलभद्र याजी (बिहार): माननीय बाइस चेयरमैन महोदय, **मैं** इस भूमि अर्जन संशोधन विधेयक की ताईद करता हूं । अभी इस विधेयक पर बोलते हुए हमारे कुछ विरोधी दल के सदस्यों ने आपत्ति की है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इस तरह से विधेयक का लाना वाजिब नहीं है । इस सदन में यह मांग भी पेश की गई है कि इस पर बहस न हो इसको वापस ले लिया जाय । जो समाजवाद के विरोधी हैं उनकी दलील तो मैं समझ सकता हूं लेकिन जो अपने को समाजवादी कहते हैं कम्युनिस्ट कहते हैं वे भी दबी जबान में इस विधेयक का विरोध करें तो आश्चर्य होता है । हम जिस समाज की कल्पना कर रहे हैं उस समाज में सारी जो जायदाद है भूमि है कल कारखाने है—सब समाज के हो जाएंगे । वे लोग भी हैं जो सरकार पर यह दबाव डालते हैं कि जितने केन्द्रीय कर्मचारी हैं राज्य के कर्मचारी हैं या जितने पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले हैं सब कर्मचारियों को मकान देने चाहिएं कल-कारखाने और स्कूल खोलने चाहिएं

और साथ ही सरकार को यह अधिकार नहीं देना चाहते कि वह भूमि पर अधिकार करके इन चीजों का निर्माण करे। अंग्रेजों की उपमा दी गई है। उस समय तो विदेशी सरकार थी। वह तो सिर्फ केन्टोनमेंट बनाने के लिए यह सब करती थी लेकिन आज तो सरकार परिकल्पना को चला रही है योजना के हिसाब से काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की सारी बातें मानी जातीं तो हमने जो जमींदारी प्रथा का विनास किया लैंड रिफार्मस किए, वे नहीं हो पाते। सुप्रीम कोर्ट का यह काम है कि वह हमारे कानून में जो नुक्स हों कमी हों उन्हें बतला दे लेकिन उसके बतलाने के साथ साथ मौजूदा सरकार के संविधान में जो कर्तव्य है उसका मकसद क्या है वह भी सुप्रीम कोर्ट को समझने की जरूरत है। मैं सुप्रीम कोर्ट की समालोचना नहीं कर सकता और न करना चाहता हूं लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट की बात को हम हर बात में मानते तो बहुत सी चीजें जो कांस्टीट्यूशन में हैं नहीं कर सकते थे। वाइस चेयरमेन साहब इस हिन्दुस्तान में न कांस्टीट्यूशन रहेगा न कोई विधान रहेगा, यहां एक ब्लडी रिवोल्युशन होगा जो हमको भी खत्म करेगा और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी खत्म करेगा। इस चीज के लिए दावत देना उस चीज को दबी जबान में सपोर्ट करना और फिर अपने को समाजवादी कहना कहां तक ठीक है। समाज का जितना काम होगा उसके लिए परिकल्पना के मुताबिक कोई कल-कारखाने नहीं बन सकते क्योंकि जमीन किसी की तो जायेगी। यह सही है जैसा चौरड़िया जी ने सजेशन दिया कि जो उपजाऊ जमीन है उसकी जगह पर कंकरीली जमीन ली जाय। लेकिन इसी तरह कहीं सारी की सारी फर्टाइल जमीन है तो अगर आप उसे नहीं लेंगे तो सब काम बन्द हो जायेगा जो ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को जो समाजवाद में विश्वास रखते हैं यह बताना चाहता हूं कि एक वक्त ऐसा आने वाला है कि सारी जमीन समाज की होने वाली है। इसको कोई रोक नहीं सकता न शासन रोक सकता है न माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज रोक सकते हैं। वह चीज आने वाली है। इसलिए हमारी सरकार बराबर समय के प्रवाह के मुताबिक काम करती है। हमारी सरकार कछुए की गति से चलती है, लेकिन चलने की कोशिस जरूर करती है। इस विधेयक के जरिए से जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे नुक्स बताए उनके लिए सरकार को इस सदन को और हम को यह अधिकार है कि हम कांस्टीट्यूशन में संशोधन करें। यह हमारा अधिकार है। इसलिए इस बिल को लाया गया।

राजनारायण जी अपने को समाजवादी कहते हैं। मैं उनको समाजवादी नहीं मानता। मैं उनको स्यूडो सोशलिस्ट कहता हूं पर्वर्टेड सोशलिस्ट कहिए। सोशलिज्म की बात तो करते हैं लेकिन जो कुछ भी सरकार समाजवाद के रास्ते पर चलने का काम करती है—चूंकि कांग्रेस सरकार करती है—उसकी मुखालिफत करते हैं। इसलिए मैं सदस्यों से कहूंगा कि समय के मुताबिक जो हमारी सरकार चलने के लिए इस तरह के भूमि अर्जन बिल वगैरह लाती है उसका समर्थन करें। एक दिन सारी-की सारी जमीन को हम समाज को देंगे सब पर सरकार अधिकार करेगी कल-कारखानों पर करेगी। इसलिए आज तो हमारे डैवलपमेंट के ख्याल से स्कूल के कालेज के लिए कारखाने के लिए जो सरकारी कर्मचारी हैं और दूसरे लोगों को भी मकान देने के लिए जो यह सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन विधेयक लाई है सदन के सदस्यों को इसको स्वीकार करना चाहिए। यदि वे स्वीकार नहीं करते हैं तो माननीय वाइस चेयरमैन साहब समाजवाद का जो फ्यूचर है भविष्य है वह काला मालूम पड़ता है, ग्लूमी मालूम पड़ता है। इस तरह का अच्छा विधेयक जो समाजवाद के रास्ते पर सरकार को ले जाता है उसकी मुखालिफत

[श्री शीलभद्र याजी]

हो तो न जाने समाजवाद कब आएगा। थोड़े से कल-कारखाने बनाने के लिए अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान देने के लिए यदि सरकार को अधिकार न दिए जायें और उसमें सुप्रीम कोर्ट रुकावट डाले तो यह ठीक रास्ता नहीं है इससे समाजवाद का जो भविष्य है वह अन्धकारमय होगा और जो रोकने वाले हैं चाहे वे सुप्रीम कोर्ट के जज हों चाहे हम हों सबका भविष्य अन्धकारमय होगा। इस देश में बुलडी रिवोल्यूशन होगा। उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सरकार समय के मुताबिक चलती है और संविधान में संशोधन लाती है जिसका इस संसद को अधिकार है और हमको अधिकार है। मैं माननीय सदस्यों से पुरजोर अपील करूंगा कि एक मत से इस विधेयक की ताईद करें।

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, it is not clear exactly what the Government's mind is in this matter, particularly in the Congress Party. We have heard the two distinctly contradictory views of two Members of the Congress Party, *viz.*, the hon. friend who just spoke before me and the hon. Mr. N. Patra. In particular I would like to ask through you, Mr. Patra where he was when the Seventeenth Amendment was stampeded through this House. In spite of so much protest in the Select Committee, when there was Satyagraha right up to the door of Parliament and elsewhere, Government would not take the advice and perhaps the result has come which is sought to be remedied by this sort of amendment. Also, very often in this House references were made to the land deals which were going on in Delhi, to the malpractices that were being indulged in by a clique who were managing the affairs of the lands around Delhi. Government would not wake up and the result we have seen in the last general elections. The hon. Minister got up to intervene when the hon. Member, Mr. Chordia, was making his speech. I would like to congratulate Mr Chordia for the very well thought oui and reasoned speech that he made. But I would also like my friend Mr. Chordia, and his friends in the new set-up in Delhi who are in power to remember the suggestion made by the hon. Minister. He suggests to them to enquire into the misdeeds of the past administration. I hope they will do so. I hope they will take a lesson from what is going to ibe done in Orissa under the new Chief Minister who has given an assurance that he will enquire into the misdeeds of the previous Chief Minister, Shri Biju Patnaik, about which he has heard -jo much. I hope the present administration in Delhi which has come into being by the popular vote will take a lesson ahd go into the misdeeds of the past administration. I hope the pattern will be the same not only in this place but everywhere where the past Governments because of their vast majority had turned a deaf ear to so many complaints that were brought to their notice.

Sir, the plea for referring a measure of this type to a Select Committee is a plea that cannot be refused on any reasonable ground. This Government has made a mess of land legislation only on one plea and that is similar to what my hon. friend Mr. Yajee, was making. The only thing that he omitted to say was, if the Supreme Court comes in the way, abolish the Supreme Court. Without putting it in so many words he said everything else. He only left out the conclusion. His case was that only. I know there are a number of Members in this House . . .

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: I never suggested the Supreme Court should be abolished.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: I think I am very clear. Sir, you understand what I mean to convey. Perhaps Mr. Yajee is not able to follow what I am saying.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: I said what would happen in the future.

SHRI D^HYABHAI V. PATEL: You will ha^e to change many of your views.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: You will be nowhere in the next gene, ral elections

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: I am going to be here whether you like me or not. You will have to bear with me for many years to come.

Sir, I was just pointing out before I was interrupted that land legislation as it exists in this country needs to be reviewed. I do not know whether Mr. Yajee knows, I do not know whether the hoi. Minister knows, but under the law of the land as it exists in the province of Bihar from where my friend, Mr. Yajee, comes, anybody can go and occupy a vacant land and pay land revenue for two years. If lie has paid land revenue for two years, he has established his title to land. This is what I have been told by people who have done s°J they have shown me places they have occupied. I am glad to say that they are producing good grain on land which was lying vacant. Even Shri J. P. Narayan who comes from that province has not been able to do so with all the Bhoodan lands that have been put at his disposal. If the hon. Minister has an open mind on these things I would be very glad to take him and show him these places. But the point I am making is—whether it is right or wrong is a different matter—that land legislation in this country needs to be gone into not in this hurried manner as we do but it needs to be put on a rational and reasonable footing. I had pointed out this at the time the 17th Amendment was being moved in this House. I pleaded but a legal luminary sitting on the opposite side pressed that since this was going to the Select Committee why I was objecting. I had to remind that legal luminary that if we accepted the proposal for sending it to a Select Committee it meant that we accepted the principle of the Bill, and we opposed it. But Government was not in a mood to listen to reason, and therefore we have got this historic judgment of the Supreme Court.

What is Government's reaction and what does Government propose to do? I agree very much with some of the observations of Mr. Chordia. I am sure that many hon. Members must have been approached by local people from Delhi who have been affected by the proposed Bill. They do not know where they will stand. They have been given assurances. They have purchased land. Under this Bill what is going to be the position of the land? What is going to be position of the structures that have been built on them? In the 17th Amendment it concerned mainly Government acquiring land in rural areas. Here you have gone a step further, and they want to take away land in built-up areas without specifyig what compensation they will give. I am afraid th'e whole principle of the Bill is misconceived and in the same spirit in which the 17th Amendment was stampeded through this House. In Gujarat I had pointed out last time that wherever somebody wants to start agriculture on a co-operative basis . . .

SHRI ANNASAHIB SHINDE: I am sorry to intervene, but may I draw his attention that there is nothing in the Bill which adds to the previous position as far as the acquisition of land is concerned on which buildings are constructed? If you are referring to the point that as between the Supreme Court judgment and the promulgation of the Ordinance some constructions may have come up, as far as that position is concerned there is already a provision in the law for *bona fide* constructions, an^ the Collectors can go into that and they can perhaps award a reasonable compensation.

श्री विजयकुमार रामलाल लजी धौरडिया : प्रश्न यह है कि जो जमीन 1959 ई0 में धारा 4 (1) के अन्तर्गत नोटिफाई कर

[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया]

दी उसको कालोनाइजर्स ने उन से खरीद लिया और कालोनाइजर्स ने मकान बनाने वालों को दे दिया और मकान बनाने वालों ने धारा 4 का नोटिस होने के बावजूद भी उस पर अपनी इमारत खड़ी कर दी तो धारा 4 के अन्तर्गत उसे एक्वायर करने का जो काम हुआ उसके चलते उनके मकान का क्या होगा क्यों कि आप कम्पन्सेशन देंगे 1959 ई० के अनुसार ।

SHRI ANNASAHIB SHINDE: That is a different thing.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: I was just trying to point out exactly what my friend, Mr. Chordia has said. I just wanted to refer it and go on to similar matter that came in the 17th Amendment. In Gujarat in several places people came out with the idea of starting co-operative farming, and in the position that existed in Gujarat, people could be compelled to join a co-operative under the law that existed and which was sought to be given official sanction from here under the 17th Amendment. I feel this was wrong. An agriculturist could not be compelled to join a co-operative or a collective. We have got a lot of people who are still enamoured of collectives, though the results neither in China nor in Russia seem to show that that is the better way of cultivating, that it produces more than the initiative of the farmer who produces better on his own.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: This you can argue with Mr. Bhupesh Gupta.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: You better take him on your side because he seems to be your guru, your ideal, and I have repeated here in this House that he was the driving force very often in this matter behind Shri Jawaharlal Nehru. If you accept the position, my case is proved, that does not mean I will ever agree with him. I think it is fundamentally wrong to do that. Mr. Bhupesh Gupta has got funny ideas, ideas which I do not like. He is certainly welcome to those ideas as anybody else is. But 1 am pointing out the fact which neithei Mr. Bhupesh Gupta not the hon. Minister can deny that after 50 years or 60 years of communism Russia does not produce enough food from the vast land that it has and it has to import food from America. Similarly, in China they have gone the same way. They do not produce enough for themselves and they have to purchase from abroad. If they do not get directly from America, they purchase through France or some other country; they do purchase. Let us recognise the fact. Therefore, the conclusion is that better food production will not take place under conditions that exi ". in China and in Russia but will onlr take place where there is a free and protected farmer. That is what we want; that is what Gandhiji told Therefore under Gandhiji's advice, the fundamental right of the farmer was promised to be protected at the Karachi Congress where the Resolution on Fundamental Rights was moved by no less a person than Jawaharlal Nehru himself. It was only afterwards . . .

श्री शीलभद्र याजी : गांधी जी ने बराबर कहा कि सारी जमीन समाज की है और कभी नहीं कहा जैसा आप कहते हैं । ये स्वतंत्र पार्टी . . . .

श्री डाह्याभाई व० पटेल : मैं नहीं मानता हूं । आप जितना चिल्लाते हैं चिल्लाओ । हम मानते हैं कि जो आश्वासन इस देश के लोगों को जवाहरलाल नेहरू ने दिया वह पूरा नहीं किया । आप कराची कांग्रेस में गये थे , वहां क्या थे कौन थे मैं नहीं जानता लेकिन गांधी जी के बाद जवाहरलालजी ने क्या किया कि थोड़ी

सी सत्ता आने के बाद उनका दिमाग फिर गया, रशिया गये उससे फिर गया, चाइना गये उससे फिर गया । क्या हुआ, वे बातें भूल गये, उन से फिर गये । जो आश्वासन दिया था कि किसानों की उन्नति करना चाहते हैं । लेकिन वे बड़े बड़े किसानों को आगे करना चाहते थे, नहीं तो बड़े जमीदार रेजिस्ट करेंग । हमारे अहमदाबाद के एक मिल वाले के पास एक प्रौटेक्टेड फार्म है, उस में सेवेन्टीन्थ्याअमेन्डमेन्ट नहीं लगता है, लैन्ड एक्विजिशन नहीं लगता है । हमारे माननीय मिनिस्टर साहब कभी कभी अहमदाबाद गये होंगे । अहमदाबाद से वीरमगांव तक मोटर के रास्त में प्रोटेक्टेड फार्म मिलओनर्स के आते है, उनको कोई छंता नहीं है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने उनको छोड़ दिया । ठीक है उन को पैसा चाहिये चुनाव के वास्ते तो उनको प्रोटेक्शन दिया है । बेचारे गरीब किसान को प्रोटेक्शन नहीं दिया । याजी जी यहां चिल्लाते हैं । उनको यह बात नजर नहीं आती है । जो बात सामने आती है वह उनको नजर नहीं आती है । सोशलिज्म की बात कहते है । सोशलिज्म किसी का माल छीन कर ले लेने को नहीं कहता है । सारे देश का, हिन्दुस्तान का पैसा आप छीन ले तो यह हिन्दुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा । यह बात हमारे समझने की जरूरत है । हमारे मित्र श्री याजी मंत्रियों को सर्व करते हैं ।

श्री शीलभद्र याजी : स्वतंत्रपार्टी वाले एसे ही बात करते हैं ।

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: No country can rise by confiscating what everybody has got and distributing it. It is only by the production of more wealth that the condition of our agriculture and of our economy can be improved. I do not see anything in this legislation that is going in that direction.

I feel that the whole land policy of our Government is misdirected and this method 01 bringing up sucn legislations again and again in hot haste is wrong. I would still request the hon. Minister to refer this to a Select Committee. Let the matter be reconsidered and measures taken which do not come up before the Supreme Court again and again and we have trouble with them. Fortunately, in this House today we have eminent lawyers who are Members of this House, who have been advisers to the Government, to whose advice the Government would normally have listened but who were not consulted when the Seventeenth Amendment was sought to be rushed through. I know. Let the Government reconsider the matter. Otherwise, the people of this country will remember the hon. Mr. Yajee and people who think like him. The Congress has ceased to govern nine States of this country already and the day is not far off when they will be out of the other nine States.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): I have received requests from some other hon. Members today who want to take part in this discussion. I am prepared to accommodate them. But I would request them to limit their remarks to five minutes each. Shri Abid Ali.

SHRI ABID ALI (Maharashtra): Thank you, Mr. Vice-Chairman.

I support the amending Bill. But while doing so, I would request the hon. Minister kindly to ensure the proper implementation of the Act as it exists and as it would be amended. Of course, we are pledged to socialism. But socialism does not mean injustice being done to poor people, particularly those who possess lands of small holdings, they have to receive more consideration. The way in which the whole land acquisition proceedings are conducted displeases many people, puts them into many and considerable inconveniences. Lands are notified for acquisition and for years nothing is done. In some cases, possession also has been taken technically but the amount is not paid. There are some

[Shri Abid Ali.] charity trusts to whom these lands belong and some of the lands under acquisition are mortgaged. The owners of these lands have to continue paying the mortgage interest and there is no end to it.

Mr. Dahyabhai Patel is going. I wanted to make a reference to some of the charges that he made.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: I went out to drink some water.

SHRI ABID ALI: He can come later, Sir. I will come to his points subsequently. I hope I have enough cf
time.

I would request the hon. Minister kindly to ensure taking quick decisions. So far as acquisition in public interest is concerned, it has to be done. I would request the hon. Minister kindly to communicate to all the State Ministers about thi$_s$ and bring pressure on them, in the Central territories and other places everywhere that quick decisions should be given. In Delhi for 12 years some matters are pending before the tribunals in appeal. There are High Court decisions given. On the basis of that, I hope that quick action would be taken. Now, some of the lands in Delhi were acquired under the emergency clause under this Act. I know that still on some nothing is done. The emergency clause was applied and for eight years not a piece of brick has been placed there, no building has been constructed, ana nothing is happening, and the land is just lying vacant; the tillers have been deprived of possession.

Now, with regard to my hon. friend, Shri Dahyabhai Patel, I am sorry he has gone away . . .

SHRI ANNASAHIB SHINDE: No, he i$_s$ here.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL; All the Congressmen are short-sighted, 1 think.

SHRI ABID ALI: Of course, they have a strong vision. He is not in seat.

The hon. Member made some charges. I wa$_s$ going to make a reference to them, firstly, to what he said regarding the enquiry in Or It is good. I would like that the enquiry should be started in a full-fledged manner against everybody, everywhere, official and non-official, against whom charges are mentioned by anybody. And I think Mr. Dahyabhai Patel and many oi associates will be found much moj • guilty. I know Mr. Dahyabhai Patel for long. I know that he was serving in an insurance corporation as a junior officer. I know that he is a wealthy man today.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: I am not a wealthy man. I was a senior officer in the Oriental Lift Insurance Company. Your information is wrong. I am not a wealthy man.

SHRI ABID ALI: May be a senior officer. About the wealth that he i possessing, his returns are available from the Income-Tax Department. How he got in possession of such bijj wealth and how he used the good name of the great leader of India is being . . .

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: J protest.

SHRI ABID ALI: Protesting . . .

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: I would like any one man to say that I ever used my father's name. It is the present Congress Ministers who are allowing that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): No insinuation, please.

SHRI ABID ALI: Of course, no in-sinuation.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): Speak on the Bill.

SHRI ABID ALI: Then why did you allow him to make a statement about Congressmen, Orissa and enquiry?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): You should have objected at that time.

SHRI ABID ALI: I am following the standard here. What I was submitting was thai the people who make charges are themselves sitting in glass houses.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: I wish he would make those charges outside and then see what happens.

SHRI ABID ALI: I will repeat and prove my words. If the hon'ble Member is prepared to appeal to the Chair and an opportunity is allowed :o me, I am prepared to prove what I say because I know the ins and outs of everything. Therefore, with regard to the statement that he made, I was suggesting that he is himself in a glass house. It is no use saying that the Congress has lost. It is we Congressmen who were responsible for कांग्रेस की सरकार ने हिन्दुस्थान की जनता की सरकार को सरकार बनाया है are responsiDie ior tnis. mere was no authority, power or party in India which could compel us at that time. We have confidence in the people. We have given them the Constitution and they have exercised their right. We are happy about it. What is the use saying every day that this Ministry has gone, that Ministry has gone, so many Ministries have gone? The Ministries will go. The whole world will perish. But may I submit to him, let he and his associates always remember that their hands are not clean?

श्री जगत नारायण (हरियाना) : वाइसचेयरमन साहब, मैं वजीर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं बड़े अदब के साथ कि यह इतना पुराना ऐक्ट 1894 का है, जिसको आज बने 70, 72 साल हो गये हैं और पिछले साल 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अटेंशन दिलाया था कि इसमें कुछ लेक्युना है, तो एक साल के अर्से में क्यों नहीं इस सरकार ने नया जामे बिल तैयार किया इस सारे लैंड अक्वीजीशन प्राब्लम को हल करने के लिये। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वजीर साहब को देना चाहिये क्योंकि अब जो बिल पेश किया जा रहा है वह सुप्रीम कोर्ट ने जो लेक्युना बतलाया था, उसको दूर करने के लिये पेश किया है। मैं समझता हूं कि यह बड़ी गलत रवायात हैं। हमारी जो सब से बड़ी अदालत है, वह कोई फैसला करे और हमारी सरकार इतने अर्से के बाद भी कोई जामे बिल तैयार न करे, तो मैं समझता हूं कि उनका यह अटीट्यूड बड़ा ही नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं समझता हूं कि इस बिल को पास कराने के बजाय अगर हमारी सरकार एक जामे बिल तैयार करे जैसा कि वजीर साहब ने खुद अपनी तकरीर में कहा कि वे एक कांप्रिहैंसिव बिल लाना चाहते हैं और एक पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाना चाहते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगले सेशन तक वे पार्लियामेंट्री कमेटी मुकर्रर कर दें और एक कांप्रिहैंसिव बिल ले आयें और फिर जो लोगों की तक्लीफात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए वे उसको पब्लिक ओपीनियन के लिए सर्कुलेट करें। इस तरह जो जामे बिल तैयार होगा उससे लोगों को रिलीफ मिल सकेगा।

मेरे भाई चौरड़िया साहब ने दुरुस्त कहा कि दिल्ली शहर में ऐसे लाखों की तादाद में परिवार हैं जिन्होंने कालोनाइजर्स से जमीनें लेकर अपने मकान बनाये हैं। अब वे इस दुविधा में हैं कि पता नहीं इस बिल के पास हो जाने के बाद उनका क्या हश्र होगा। वजीर साहब ने इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया है। मैं चाहूंगा कि वे इसका तसल्लीबख्श जवाब दें क्योंकि लोगों ने कालोनाईजर्स से जमीनें खरीदीं और अपने

[श्री जगत नारायण]

मकान बना लिये और उनको यह डर है कि हमारे मकान गिराये जायेंगे और हमको नुकसान पहुंच जायेगा । तो मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी चीज है जिस पर हमारी गवर्नमेंट को पूरा ध्यान देना चाहिये और इसकी तलाफी करनी चाहिये ।

अब मैं वजीर साहब की नोटिस में एक बात और लाना चाहता हूं और वह यह है कि दिल्ली के बारे में मुझे जाती तजुर्बा है क्योंकि मेरे लड़के और दामाद ने भी जो यहां हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटीज बनी हुई है उनमें रुपया जमा कर रखा है । लोगों ने लाखों रुपया उन सोसायटीज में पांच पांच साल से जमा कर रखा है । गवर्नमेंट ने उन सोसायटीज को यह भी आश्वासन दे रखा है कि हम तुम्हारे लिये जमीन अक्वायर कर रहे हैं और यह भी बता दिया है कि फला जगह जमीन दी जायगी । मगर अभी तक वह जमीन उनको नहीं मिल रही है । आठ आठ साल से लोगों ने अपना पैसा दिया हुआ है और उन सोसायटीज ने लाखों रुपया लोगों के पास से जमा कराया हुआ है लेकिन उन सोसायटीज को जमीन मिल नहीं रही है । गवर्नमेंट ने वह जमीन अक्वायर कर ली है लेकिन वह सोसायटीज को मिल नहीं रही है क्योंकि सोसायटीज ने गवर्नमेंट के पास लोगों से लाखों रुपया ले कर के जमा कर दिया है । इससे अभी तक लोग मारे मारे फिर रहे हैं न वे अपना मकान बना सकते हैं और न कोई अलाटमेंट होता है । मैं चाहूंगा कि वजीर साहब इस मसले में भी जरा बतलायें हाउस को कि क्या वजह है कि जब उन्होंने जमीन अक्वायर कर ली है जब सोसायटीज से उन्होंने रुपया ले लिया है तो आज उन को जमीन क्यों नहीं अलाट होती ताकि लोग अपने मकान बना सकें । लोगों ने पांच पांच दस दस और बीस बीस हजार रुपया अपनी सोसायटीज में जमा कर रखा है और उनको रुपया जमा किये हुये छः छः और आठ आठ साल हो गये हैं फिर भी उनको जमीन मकान बनाने के लिये अलाट नहीं की जा रही है । तो इस तरफ भी वजीर साहब को ध्यान देना चाहिये ।

अब मैं वजीर साहब को अपने पंजाब के नवाशहर की एक मिसाल देना चाहता हूं । वहां पर एक शूगर फैक्ट्री बनाने का फैसला किया गया और गवर्नमेंट ने उसके लिये जमीन अक्वायर कर ली । उसको नौ साल हो गये हैं लेकिन वह शुगर फैक्ट्री अभी तक बनने को नहीं आती है । वहां पर जो लैंड अक्वायर की गई है वह वैसे ही पड़ी हुई है । न उसमें अनाज बोया जाता है और न उसमें फैक्ट्री लगती है । एक तरफ हम यह सोच रहे हैं कि हमारे यहां जो अनाज की कमी है उसको पूरा किया जाय और दूसरी तरफ हालत यह है कि जो जमीन किसी इंस्टिट्यूशन के लिये गवर्नमेंट अक्वायर करती है वह सालों तक बेकार पड़ी रहती है उसमें न अनाज बोया जा सकता है और न कुछ हो सकता है । इसके मुताल्लिक भी वजीर साहब को ध्यान देना चाहिये ।

एक बात मैं और उनकी नोटिस में लाना चाहता हूं कि जो वे जमीन अक्वायर करते हैं उसमें वे मालिकों को कुछ पैसा दे देते हैं, चाहे दो साल, पांच साल या छः साल के बाद दें, मगर जो टेनेंट्स बेचारे बेदखल हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है । उनको बड़ी तकलीफ होती है वे मारे मारे फिरते हैं और उनको सब जगह भागना पड़ता है । तो जो आप आगे लेजिस्लेशन बनायें उसमें यह भी रखें कि जहां आप मालिकान को कम्पेंसेशन दें वहां जो टेनेंट काफी देर से वहां बैठा हुआ है उसको भी पूरा मुआविजा दें ।

इसके साथ साथ मैं यह चाहता हूं कि वजीर साहब कम अज कम इस बिल पर जवाब देते हुये पब्लिक पर्पज को भी क्लियर करें कि पब्लिक पर्पज का क्या मतलब है जिसके लिये यह जमीन अक्वायर की जाती है । इसको भी जरा वे साफ करने की कोशिश करें

क्योंकि इस बिल में यह साफ नहीं है कि उनका पब्लिक पर्पज क्या है । जब वे जमीन अक्वायर करते हैं तो उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, यह भी वे साफ करने की कोशिश करें ।

अब मैं सिर्फ एक बात कह कर बैठ जाऊंगा । यह जो आप कम्पेनसेशन देते हैं यह वक्त पर नहीं मिलता है और फिर जब लोग कम्पेनसेशन लेने जाते हैं तो उनके लिये बड़ी मुश्किल यह हो जाती है कि जब तक वे रिश्वत न दें तहसीलदार वगैरह को तब तक उनको पूरा पैसा नहीं मिलता है । किसी को अगर सौ रुपए मिलने होते हैं तो उसमें से कम अज कम उसको बीस रुपये देने पड़ते हैं पटवारी को या दूसरे शरिस्तेदारों को तब कहीं जा कर के उसको कम्पेनसेशन का रुपया मिलता है । इसकी तरफ भी गवर्नमेंट को तवज्जह देनी चाहिये कि जिस से आप जमीन अक्वायर करें उसको कम अज कम पूरा पैसा तो मिल जाय और यह नहीं हो कि उसको अपना कम्पेनसेशन हासिल करने के लिये जो रुपया मिलना है उसमें से वह आधा रिश्वत में दे दें तब जा कर उसको रुपया मिले । इसके लिये भी आप को कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिये ।

KUMARI SHANTA VASISHT (Delhi): Mr. Vice-Chairman, Sir, the land acquisition in Delhi has caused a tremendous amount of hardship to the people here, and as our friend, Mr. Chordia, has also pointed out as also Mr. Abid Ali, that the people have suffered quite a lot due to this procedure and negligence of the Government particularly in respect of the compensation that has been paid to them.

Sometimes the land has been acquired at very cheap rates. I think Mr. Chordia's figure of 70 p. is probably not quite correct. Recently it has been about Re. 1 or Rs. 2 and sometimes may be Rs. 3 per sq. yard.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : यह '59' के जितने नोटीफिकेशन हुए, उसके अन्तर्गत जो जमीन ली है उसके लिए 70,80 और 90 पैसे के हिसाब से दिया है ।

कुमारी शान्ता वशिष्ठ : मगर उसके बाद रिवीजन हुआ था । रिपोर्ट में है कि कई केसेज में उसको रिवाइज किया गया ।

But this fixation of land price it not equitable by any yard-stick. In the sales that have been made after acquisition of land by the Government, either by the D.D.A. or by the various other authorities, the prices have gone up from Rs. 40 to Rs. 125 or Rs. 130 per sq. yard, when the auctions of various plots of land took place. It is now Rs. 300 to Rs. 500 as Mr. Chordia said . . .

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : सिनेमा के लिए जो जमीन नीलाम की गई, उसका 500 रुपए के हिसाब से लिया गया ।

KUMARI SHANTA VASISHT: Yes, that is correct, sfar j|, ?feqr, *ifm,* |

But what I am saying is that the prices given to the land-owners who are, by and large, very poor people, have been very neglible and when the Government have added their own cost of development and other administrative costs and certain other charges, they have calculated the rate on a no-profit-no-loss basis at Rs. 30, Rs. 35 or Rs. 40 at the minimum. This great injustice and disparity and the very wrong approach to the whole question were pointed out so many years ago even when Pandit Jawahar-lal Nehru was alive. This representation was made to him by our people, but unfortunately, nothing has been done. Even when this matter of price fixation was taken up with the D.D.A., they gave some set explanations saying—"so much is the administrative cost, so much is the development charges, so much on this, etc., etc., and coming up with a fictitious figure which leads you nowhere. When a private coloniser can sell at the rate of only about Rs. 10, how is that the Delhi Development Authority can sell at the rate of Rs. 40 when they give the same sort

[Kumari Shanta Vasisht.] of services or maybe slightly more? The disparity i_n prices is very much indeed. There are many cases pending from 1958 where compensation has not been paid yet. The rates are also different in different areas in the same locality. One person, who may be influential, will get a higher rate even from a court of law, but a neighbouring person, who is not so influential, will not get ihe same rate. Secondly, even for getting an adequate price for the land acquired by the Government, everybody has to depend on litigation which the poorer people cannot afford. It is very hard for them to be able to go to a court of law and demand justice regarding the rate of compensation to be paid. This has caused a good deal of hardship to our people.

With the great expansion of the urban area in Delhi, with the influx of nearly one lakh of people every year into Delhi, with the large expansion of Government offices and Government servants' residential area in Delhi, the land prices have shot up. Also there is a good deal of speculation in land and so on which increases the land prices. All this has caused a large number of people to come into Delhi and construction activity has expanded enormously. And the por peasants unfortunately have been tempted to sell their land, as everybody else, and make money quickly because of the great demand and hunger for land in Delhi. The result is that the Government has been put in an awkward position because they cannot stop all activity and the unauthorised people make construction and it is very difficult for the Government either to regularise them or demolish them. Also there has been a great deal of negligence in passing or approving construction plans, etc., early, and this has created a lot of difficulties, hardship and heartburning to the people in Delhi because they cannot make construction within the rules; and the rules are very defective. Compensation is not paid; in time; lay-outs are not prepared in time; and because of all these, at every step, the people have faced a lot of difficulties. Mr. Dahayabhai Patel is not here now. But I would like, to contradict certain things he has said. He said that the colonisers in Delhi have been responsible for the results in the elections. He, at ′ least, coming from the Swatantra Party, ought not to have worried about the reasons for the election re suits in Delhi. It should be our problem and our worry rather than his problem. If anything, he should be happy that at least some other party has won. But it is true that to a large number of pople who come into Delhi—about a lakh of people every year—and who have constructed houses, when their houses are demolished or when they live with a feeling of uncertainty or fear that their houses may be demolished or when they are being harassed by the Inspectorate and other people when they have undertaken construction, enormous hardship and irritation i^s caused. The expansion of this town should not be allowed at the rate at which it is being allowed. We should develop some satellite towns. We should arrange to shift this population into other smaller towns around Delhi and revive other towns like Agra and Meerut and other smaller towns. They should be revived rather than that everybody should come into Delhi and raise the price of everything here, and create difficulties for themselves as well as for others. So my suggestion is that the whole question needs to be examined seriously and at very great length. A through study should be made and compensation should be fixed and given in a very equitable and proper manner. I do not agree with Mr. Yajee when he says that "We want socialism, but we are only taking away land from the poor people and giving it to the rich people; what sort of socialism is this? No money is paid to these people for years and years and they are expected to go into litigation and become even more bankrupt and the land also passs into the hands of cinema-owners or hotel-owners or

other rich people who have money to buy it." There is always this question of public purpose, but this also should be defined clearly. This has been misused quite often. Sometimes land is given for a certain industry, but the industry sells that land to somebody else and makes a profit out of it which the Government could have well done. These are the many difficulties. I think there should be a time-limit within which compensation and other procedures should be completed. I would suggest that within one year, everything should be completed. It should not go on for thiee years or four years or five years. If the Government servants were not to get their salaries for five years or so, then I would like to know how they would feel about it. If the question of their promotion is delayed for five years or so, I would like to know how they would feel about it. They want their terms and conditions and everything to be right and proper, but when it comes to paying compensation, they take four years or five years. I think it should not take more than six months and not more than one year at the most.

I would also like to emphasise before the hon. Minister that when, large tracts of land are acquired by Government, those peasants become absolutely landless and pennyless and sometimes the compensation that is paid very late is also squandered away because they are neither qualified nor are they skilled artisans or engineers or doctors or qualified even for semi-skilled jobs. So every one of these persons and their boys should be given some sort of skilled or semi-skilled training so that they are absorbed in jobs around that colony' or industry for which the land was acquired. They should be made partners in the industries that are started on the land that is acquired from them and the compensation money should be made part of the capital because otherwise these poor people would misuse it. If the compensation money is paid by way of shares in the industry, to be set up on their lands, then they may get some money from those shares; they become partners in the industry and their boys can be absorbed in jobs there after the necessary training is given to them. So along with the land acquisition programme, there must be a programme for the rehabilitation of the people whose land is acquired. This will pose a very serious problem before you and this requires very serious thought and planning, because when their land is acquired and compensation money is paid to them, they are likely to squander it away at once—to eat, and drink and be merry—and- after that, they will be absolutely helpless, without any qualification or training for any other job. So this problem should be given serious consideration and the whole question should be seriously examined.

Thank you.

SHRI ANNASAHIB SHlNDE: I am thankful to hon. Members and to this august House for enlightening me on a number of issues involved in this Bill. During the course of this debate a number of helpful suggestions have been made by hon. Members. I was there also in the Lok Sabha when the debate took place and I also persued the previous debates when on a number of previous occasions this Act was being amended and discussions took place in this House. I find that a large number of Members of this House take considerable interest when the land legislations are being amended and that is rightly so. Some Members opposite have been critical but I am thankful to all of them for participating in this debate. This has helped me to understand the depth of feelings of the Members on this particular Bill. I am also aware of the shortcomings of the Land Acquisition Act and particularly the way the law is implemented in practice. As I mentioned in the other House, one of my own lands which I was cultivating as a tenant, part of it was acquired and the compensation

[Shri Annasahib Shinde.] was paid after 10 years after possession was take© over. So I know of the administrative delays in implementation too. A number of Members, specially Mr. Abid Ali, Mr. Jagat Narain and Kumari Shanta Vasisht referred to the administrative delays and a number of other problems. I think Kumari Vasisht made a very important point about the problem of rehabilitation. As a result of land acquisition measures, a number of people are displaced. As we know in our country there are no alternative avenues for employment easily available and as soon as these persons are displaced as a result of acquisition of their lands, they are practically thrown on the streets and they have to face numerous difficulties especially poor people. I quite agree with the suggestion of Kumari Vasisht that the programme of land acquisition should be associated with or made an integral part of the programme of rehabilitation. It is a very helpful suggestion and needs examination. As far as the Act is concerned, there are certain other aspects and difficulties. For instance there is the complaint about adequacy of compensation and that is a very reasonable complaint, m a number of cases the people had to undergo considerable hardship as a result of inadequate compensation and sometimes extremely fertile and rich lands are acquired for non-agricultural purposes. After the lands are acquired, for a considerable time the lands remain fallow or unused. All these require to be looked into.

While making my preliminary observations, I had suggested that the Government has decided to set up a Committee of Members of Parliament to go into this entire scheme of the Act. The Act is one of the oldest in our Statute Book. It "was passed in 1894, about 70 years back and a number of anomalies have come into it as a result of the working of the Act. Though the Act has been amended many times it requires fresh look and that is why I have suggested that the entire scheme of the Act needs re-examination. Some time back the Law Commission, with which some very eminent legal experts of this House were associated, went into this problem and they have also made a number of useful suggestions. Recently in my Ministry, under the Chairmanship of Mr. Sivaraman, Secretary in my Ministry, a Committee went into the implementation of this Act and it has also made a number of suggestions. Together with the suggestions of the Members of this House, the suggestions of the Law Commission and these of the Committee of administrators, the Committee of Members of Parliament would be in a position to make quite useful recommendations for amending the basic framework of the law.

Shri Yajee referred to a very important aspect of the law and brought to the notice of the Members the basic scheme as to why a Land Acquisition Act is necessary. Most of the countries of the world have similar acts in their own countries. Now our towns are developing fast; we are developing our industries. We require lands for our irrigation development. We require lands for fertiliser factories and various other projects. It is the need of the times that lands should be made available for the development projects. So it is no use opposing the basic scheme of the Act as such, though as I have suggested, while implementing the Act, the difficulties may be taken into consideration as to how to avoid the hardship caused to the common people, common farmer and that should be taken into consideration but as far as the basic approach to the problem is concerned, I do not think we should take any other view.

As far as the proposals before the House are concerned, much of the criticism which was made by hon. Members was wide off the mark. That did not actually concern the provisions which are before the House. I must say that though Mr. Chordia made a

number of suggestions, it also escaped his notice that there are also very healthy provisions in the amendment. I do not know why it escaped his attention.

SHRI V. M. CHORDIA: About 3 years? I have given amendment for one year. कह रहा था परन्तु घंटी बज गई थी इसलिये यह सोचा कि यह बात फिर कहूंगा। बातें तो बहुत सी कहनी हैं अभी मौका लूंगा।

SHRI ANNASAHIB SHINDE: As far as one of the important provisions of the Bill is concerned, for instance, we have made a provision that the declaration under section 6 must come within a period of 3 years after the notification.

SHRI V. M. CHORDIA: it is too much.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: That can be looked into. As the Act stands to-day, there is no time-limit prescribed and this is a considerable improvement.

SHRI V. M. CHORDIA: It implies that it should be as soon as possible. It does not mean that it should be 10 years. The lethargo and red-tapism have resulted in delay.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: We are going into the basic framework of the law and at that time the suggestion of the Member can be taken into consideration. I must confine myself to the specific provision in the Bill. As far as the old Act was concerned, there was no specific time-limit prescribed between the issuance of the notification under section 4 and the declaration under section 6. This is a substantive improvement on the existing provision and so we should welcome it.

As far as the provision for interes'; is concerned, that is a very salutory provision. As the law stands to-day, even if there is delay in the notification, the owner is entitled to get the value of the land, as per the provision under Section 23 of the Act, that is, he gets the market value but the market value, which prevails on the day when the notification under Section 4 is issued, and according to that compensation determined under provision 23. We have made a provision here that as far as pending cases are concerned, if the delay is beyond 3 years, then the owner would be entitled to interest at 6 per cent, per annum on the price of the land, that is the market value which is determined as per law. This is also a very welcome suggestion and the Members should support this.

1 P.M.

Then, Sir, there is one important point which has been made by some of the hon. Members. Some impression has been created as if we are trying to circumvent the judgment of the Supreme Court. May I humbly submit that we respect the judgments of the Supreme Court? There is no attempt whatsoever to show any disrespect to the finding of the court. But, Sir, at the same time I must say that as far as Parliament is concerned, Parliament has the inherent power or prerogative to make laws. It is for the courts to interpret the law, but so far as making law is Concerned, it is the inherent right of this body, and this is done in every country. Even in the U.K., for instance, from which we have inherited our parliamentary system, even the U. K. Parliament sometimes found that in order to nullify the effect of the decisions of the House of Lords they had to enact legislation. For instance, I may refer to old history because it was a very historic case. The House of Lords gave a decision in that well-known case Queen vs. Leatham and, as a result, Parliament had to enact the law, the Trade Disputes Act of 1906. Now the purport of that law was to nullify the effect of the decision of the House of Lords. Similarly, Sir, in our own country the Wakf Validating Act of 1913 was passed, and it was passed in order to abrogate or nullify the effect of the ruling of the then Privy Council. So our Legisla-

[Shri Annasahib Shinde.]

ture have been exercising this power of making laws if they are found to be inadequate to meet the needs of a situation. So, even in the present case, if we are trying to amend the law, there Is no intention whatsoever to show 'any disrespect to the decisions of courts, and in this particular case, Sir, I must submit that, if we do not amend the law, there will be considerable hardship. For instance, the decision of the Supreme Court is on the point that, if there are more than one Declaration under section 6 taking advantage of the Notification under section 4, then all the subsequent Declarations except the first one are invalid. So the effect, Sir, has been this—I cite this as an instance—on the Bhilai steel plant. Now there, one Notification under section 4 was issued, and a number of Declarations followed. Now that plant has come up. A number of buildings have been constructed. A township has come up. Hospitals and roads have been constructed. Now, if the judgment of the Supreme Court remains as it is, and if we do not provide against it by amending the law, then the lands on which the buildings have been constructed and, perhaps, some of the rand on which the plant 'has been erected, they all will have to be restored to the original owners. Now it is a very difficult situation.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : मैं यह निवेदन करता हूं कि आप जितनी चाहे बिलडिंग बना लें हमें उस पर बिल्कुल आपत्ति नहीं, उसके लिये आप कानून ले आएं मगर जो अनडेवैलप्ड लैंड है जिसका खाली नोटिफिकेशन है उसको क्यों अटका रखा है ? उसको छोड़ दीजिए, उसको मत लगाइये ।

SHRI ANNASAHIB SHINDE: I will come to that. I am thankful to the hon. Member—at least he has conceded this position practically. He has conceded this position in the amendment also, which he has tabled, and I am glad he realises the importance of this.

Sinulary, In Delhi itself there is one case—I am only citing this as an instance. For instance, the Delhi Authority acquired some lands in the southern part 'of Delhi. A Notification under section 4 was issued and by a subsequent series of Declarations some lands were acquired. And on one portion of the land the Indian Medical Institute is situated. Now a number of buildings have came up and hospitals have been built. Now" if we do not amend this law, then the effect would be that we will have to restore the lands, on which the Indian Medical Institute buildings have come up, to their original owners. This is a very difficult situation now, and I hope hon. Members will realise the difficulties of this situation and support the present Bill which Is before the House.

Sir, may I draw the attention of this hon. House that even Supreme Court Justice Sarkar, while giving the judgment in this particular case—the State of Madhya Pradesh *vs.* Vishnu Prasad Sharma—said that the court itself realised the difficulty. And they, by implication, indicated that, had there been a specific or categoric provision for making successive Declarations then, perhaps, this difficulty would not have arisen. Considering that there is no specific provision for making 2 series of declarations, they said that we are interpreting the law in a particular way. Justice Sarkar says:

> "It must follow that without a specific provision more than one Declaration under section 6 was not contemplated."

I need not comment on the judgment of the Supreme Court, but the very implied meaning of this sentence is that, had there been a specific provision, the court would have interpreted the law In a different way.

Then, sir, some references have been made to Delhi's Master Plan. I am not prepared to say that no injustice might have bee$_n$ done in any individual case. Administrative lapses

might have been there, but the facts which have been given to me, they go to show that the lands which have been acquired and which are to be acquired for the Master Plan up to 1931, the figures with me show that most of the lands which are acquired have been acquired for public purposes, but the impression has gone round that large portions of these lands have been acquired for the benefit of a few industrialists or a few capitalists. May I submit, Sir, for the information of hon. Members that, of the lands which have been acquired, or which are to be acquired, the percentages of their use for various purposes, appear lik$_e$ this. For residential purposes it would be about 42.9 per cent; for major commercial purposes (including warehousing and mineral siding)—2.3 per ce$_n$t; for industrial purposes (including mining)—5.4 per cent; for Government purposes—7.4 per cent; for recreation (parks, etc.)—23.7 per cent; for public and semi-public facilities—8 per ceni; for agriculture (nurseries)—0.3 per cent; for transportation facilities (excluding railway facilities)—2.4 per *cent;* for roads 150' wid$_e$ and more, and *Nallas*—5.3 per cent; for railway land (including stations, yards and tracks)—2.3 per cent. Thes$_e$ will show that most of the lands which have been acquired or which are contemplated to be acquired for the development of Delhi are mostly for public purposes. Of course I concede the position—some of the hon. Members referred to that fact, and Mr. Patel also perhaps referred t$_0$ the point— that, good agricultural land should not be used for non-agricultural purposes. I concede that position and, in fact, *my* Ministry has issued executive instructions to the State Governments that, as far as possible, unless it is unavoidable, good agricultural land should not b$_e$ used for non-agricultural purposes. And may I take this opportunity to appeal to S ate Governments that, t'll the new law comes into force, that means, the law which we contemplate

to enact after the Committee of Members of Parliament goes into the basic framework of the law and makes I recommendations, until a comprehensive legislation is brought befor$_e$ the House, till that time at least, the State Governments will take care to see that good agricultural lands ar$_e$ not allowed to be used for non-agricultural purposes unless it is absolutely unavoidable.

Then, Sir, I also concede that in many place$_s$ lands are acquired and they lie fallow. Now we are passing through a very difficult food situation and, therefore, to allow the lands to lie fallow is really against our national interests, is a great national loss. 1 •appeal to the State Governments and to the Centrally-administratered territories and States that such lands should not be allowed to remain fallow but to have them ploughed and used, and they should be put to use for growing foodgrains.

Many of the Opposition Members, especially Shri Rajnarainji and others, have been very critical about this Bill. I can understand my hon. friend's anxiety and I know that in some cases hardship has really been caused to a number of persons. But now in many of the States the Opposition parties are in power and I think now at least the State governments will see that the Act is administered properly and no injustice is caused to the people.

SHRI ABID ALl: We cannot be sur$_e$ of that, they can misuse it much more.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: May I assure Shri Rajnarainji and others that the proposal which we have placed before the House for a re-examina-tion of the entire framework of the law will be dealing with all these points? Since this subject falls in the Concurrent List the representatives cf th$_e$ State Governments will be associated with this committee that is proposed for this purpose and we shall

[Shri Annasahib Shinde.] benefit from their advice. As a result of the advice of hon. Members who would be associated with that committee and advice of the representatives of the State Governments, it should be possible for us to suggest a very comprehensive piece of legislation which will solve all these difficulties.

श्री राजनारायण : इस बीच में आप की सरकार क्या करेगी । इस बीच में जो डिफिकल्टी जो हाईशिप हुई हमारी रिक्वेस्ट है कि सरकार को उसके बारे में अपना दिमाग साफ रखना चाहिये । आफ्टर दी डेमीज्रन आफ सुप्रीम कोर्ट, इस बीच में जो कुछ हुआ, उसके बारे में सरकार जवाब दे कि क्या करेगी ।

SHRI ANNASAHIB SHINDE: In fact, while the hon. Member was speaking I referred to this matter, if Shri Raj narainj i has in mind constructions during the time lag in between, that is to say between the time when the judgment of the Supreme Court came and when this Ordinance was enforced, i may say this. If during that time some constructions had taken. plac$_e$ then the Collector or the Court which gives awards for compensation, can take Into consideration the fact that perhaps th$_e$ owner might have put up that construction under the *bona fide* belief that this law did not apply to that construction and so it may be possible to award reasonable compensation under the existing law. There is no difficulty in the present law for awarding compensations in such cases.

Shri Dahyabhai Patel made some remarks about our approach to land reforms, I must concede that on this issue he has different views and we have different views.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: He misquoted G-andhiji.

SHRI ANNASAHIB SHINDE; We hav$_e$ different views on this issue. But may I submit that as far as the administration of the Land acquisition Act is concerned, In the committee that' we have proposed we really wish to go into all these things and that should satisfy him? The hon. Minister here, my senior colleague, was just mentioning to me and asking whether I had mentioned the fact that representatives of the State Governments will be associated with the committee that would be constituted. I would reiterate that representatives of the State Governments would be associated with that committee and all these defects or difficulties can be re-examined in the light of th$_e$ recommendations of that committee. With these observations, Sir, I commend this Bill to the House and I hope that with these clarifica tions all sides of the House will support this Bill, since this BUI has been brought forward to remove some difficulties created by the judgment of the Supreme Court.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M P. BHARGAVA): The question is;

> "That the Bill further to amend the Land Acquisition Act, 1894, and to validate certain acquisitions of land under the said Act, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN. (SHRI M. P. BHARGAVA): Now we shall take up the clause by clause consideration of this Bill.

Clause 8.—*Amendment of section 5A*

SHRI V. M. CHORDIA: Sir, I beg to move:

> 1. "That at pages 1 and 2, clause 2 be deleted."

श्रीमान्, मेरा अमेंडमेंट तो यह है कि सारा क्लाज ही हटा दिया जाय जो कि चलने वाला नहीं है । अमेंडमेंट की दृष्टि से वह तो वोट के आधार पर चलेगा। यह धारा 2 के द्वारा हमारी सरकार मूल विधान की धारा 5 (ए) (2) में संशोधन करना चाहती है । मूल 5(ए)(2) इस बात का परिचायक है कि आब्जेक्शन्स सुन लेने के बाद जो कलेक्टर

है वह अपनी रिपोर्ट पीसमील देवें या नहीं देवें । वर्तमान जो धारा है उसमें यह लिखा है :

"Every objection under sub-section (1) shall be made to the Collector in writing, and the Collector shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by pleader and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, submit the case for the decision of the appropriate Government, together with the record of the proceedings held by him and a report containing his recommendations on the objections."

तो यहां पर वह रिपोर्ट भेज सकता है "ए रिपोर्ट" का उल्लेख आया है । इन शब्दों ने ही हमारे विष्णु प्रसाद जी को सुप्रीम कोर्ट में भेजा और दूसरे दिल्ली वालों को भी भेजा और पंजाब हाई कोर्ट ने इसके लिये यह कहा कि पीसमील रिपोर्ट दे सकते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि पीसमील रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं । हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिणामस्वरूप यह संशोधन करना चाहती है "or make different reports in respect of different parcels of such land." अब इसमें भी दो समस्यायें पैदा होने वाली हैं "different parcels of such land" पहले तो मैं चाहता हूं कि यह अमेंडमेंट होना नहीं चाहिये । आप जिस आशय के लिये जो जमीन लेना चाहते हैं धारा 4 के अन्तर्गत और जिस की विज्ञप्ति प्रकाशित करते हैं, कलेक्टर की ड्यूटी होनी चाहिये कि वह एक एकजाई रिपोर्ट दे कर के उसको कार्यान्वित करे । आप यह इस लिये नहीं करना चाहते कि आप इस भय में रहते हैं कि अगर पहले 1959 या 1957 में आपने कोई नोटिफिकेशन किया और उसी में से थोड़ा हिस्सा आगे आप को जरूरत पड़ी तो कम्पेन्सेशन अधिक देना पड़ेगा और साथ ही अगर कोई मकान वगैरह बना ले तो तकलीफ होगी । पर इसकी कुछ सीमा होनी चाहिये और वह सीमा तीन साल की आप बांध रहे हैं । परन्तु मैं यह चाहूंगा कि जितनी आप को जमीन लेनी हो, उतनी ही का आप नोटिफिकेशन करें और उसकी एक ही रिपोर्ट दी जानी चाहिये और इसी दृष्टि से मैंने अपना संशोधन दिया है ।

अब आप के संशोधन में मैं एक जानकारी चाहूंगा । आप यह कह रहे हैं:

"or make different reports in respect of different parcels of such land"

पार्सेल का आप क्या मतलब लगाने वाले हैं क्योंकि जो खसरा नम्बर रहता है वह एकजाई नम्बर रहता है । 217 या 520 या जो भी खसरा नम्बर होगा वह निश्चित होगा । अब आप को अगर किसी के खसरा नम्बर का आधा हिस्सा आवश्यक है तो क्या आप उसके आधे हिस्से में करेंगे या एक खसरा नम्बर को पूरा पार्सल मान कर चलेंगे । इसमें आपका उद्देश्य तब पूरा हो सकता है जब आप पार्सल के साथ उसके छोटे टुकड़ों का वर्णन कर दें । यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो इस शब्द से झगड़े की जड़ पड़ने वाली है । यदि 217 नम्बर का एक बड़ा भारी प्लाट है और उसमें से आप एक हिस्सा लेना चाहते हैं तो "पार्सल" की परिभाषा में गड़बड़ पड़ सकती है । दोनों तरह के मत मिलेंगे । उधर के भी वकील मिलेंगे जो यह कहेंगे कि हम हिस्से को पार्सल कहते हैं और इधर के भी वकील मिलेंगे तो यह कहेंगे कि पार्सल का मतलब है एक यूनिट चाहिये, एक काम्पैक्ट पार्सल चाहिये और कम्पैक्ट पार्सल की दृष्टि से जो सेटिलमेंट का खसरा नम्बर देते हैं, वही होना चाहिये । यह झगड़े की जड़ पड़ेगी । इस लिये जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं, वह कभी आपसे होने वाला नहीं है । इस लिये मेरा निवेदन है कि आप इसको वापस ले लें क्योंकि यह उचित नहीं है । अगर आप इसको उचित समझते हैं तो मैं आपको

[Shri V. M. Chordia.]

बता दूं कि इस से आप का पर्पज़ पूरा होने वाला नहीं है । इस लिये इसको वापस करके जब नया संशोधन पेश करना हो तब पेश करें ।

The question was proposed.

SHRI ANNASAHIB SHlNDE: Sir, as far as thi$_s$ amendment of the hon. Member is .concerned, the very purpose of our bringing forward this amendment of ours is this. As I have already explained, th$_e$ ruling of the Supreme Court is there and as the present law stands, under section 5A, if the interpretation of the Supreme Court is taken further, perhaps by implication it may mean that only one report can be submitted by the Collector. In practice what happens is this. Suppose the Notificaton under 4(1) covers a number of lands owned by a number of persons. Under the provisions of section 5, objections have to be raised. Some of the owners may be interested ᵀm completing the acquisition proceedings as early as possible. Some others may be interested in delaying it by some kind of adjournment etc. Suppose in respect of a particular piece of land the report is complete and nothing further is to b$_e$ Inquired into, but there is another piece of land where the other persons who own that land want adjournment, then in such a case, all thes$_e$ cases will be held up and there will be delay against which the hon. Member himself is complaining. So there is some difficulty. That is the reason why in the present Bill .clause 2 provides for the submission of more than one report under section 5. That is the only plausible explanation, Sir, why we have brought forward this amendment.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): The Question is:

1. "That at pages 1 and 2, clause 2 be deleted."

The *motion was negatived.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M P. BHARGAVA): The question is:

"Thatc clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 *was added to the Bill.*

Clause 3.—*Amendment of Section* 6

SHRI V. M. CHORDlA: Sir, I move:

2. "That at page 2,—

(i) lines 6 to 13 be deleted;

(ii) in lines 20-21, for the words 'after th$_e$ expiry of three years' the words 'after the expiry of one year' be substituted; and

(Hi) lines 23-24 be deleted."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): These are self-explanatory and I do not think much of a speech is required.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : मंत्री जी ने कहा कि तुमने कहा नहीं, मैंने इस लिये नहीं कहा था कि मुझको कहना है ।

SHRI ANNASAHIB SHINDE: You have spoken so much but that is all right.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : सभापति जी, पहला जो चाहा गया है, वह धारा 5(1) का कांसीक्वेंशियल है । इसमें है अलग-अलग रिपोर्ट पेश करें और अलग-अलग डिकलेरेशन कराया जाय । अलग-अलग रिपोर्ट मंगवा लें या साथ मंगवा लें लेकिन डिक्लेरेशन एक में करवाने का प्रयत्न करें ।

जहां तक दूसरे का प्रश्न है उसमें संशोधन रखा गया है तीन वर्ष का । हमारे मंत्री जी कहते हैं कि उनको खुद 10 वर्ष का समय लगा, इसलिये तीन वर्ष की अवधि रखन

चाहते हैं। सभापति जी, वास्तव में टाइम लिमिट इसलिए नहीं दी जाती थी कि क्षमता रहती थी आफ़िसर्स की कि शीघ्र काम कर सकें। हम तीन साल की टाइम लिमिट देकर उनको तीन साल की छुट्टी दे रहे हैं कि तीन साल तक तुम इतमीनान से बैठे रहो। कोई केसेज ऐसे होते थे जिन पर तुरन्त दान महा पुण्य का फार्मूला चल जाता था, अब उतने को भी जल्दी नहीं निबटायेंगे। शिन्दे साहब पब्लिक वर्कर हैं' उनके मामले को 10 वर्ष का समय लगा, उनका काम नहीं होता था। रिश्वत देने के तरीके हैं। कागज पर वजन नहीं पड़ेगा तो चाहे पन्त जी हों, शिंदे साहब हों, चाहे चौरड़िया हों, काम नहीं होगा। शिन्दे साहब को अनुभव है। उनके मामले को 10 वर्ष का समय लगा और बाद में कम्पेनसेशन मिला। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं उन्हें – वे मंत्री जी हैं अब – वास्तव में जितना कम्पेन्सेशन मिलना चाहिये था वह नहीं मिला, कारण' कि अधिकारियों को वे उतना प्रसन्न नहीं कर सकते थे जितना कि करना चाहिये।

श्री अर्जुन अरोड़ा (उत्तर प्रदेश) : करना चाहिये, आपकी राय है ?

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : अगर पैसा ज्यादा लेना है तो वे नहीं कर सके। इस तरह से दूसरों को जो कम्पेनसेशन मिला होगा, उसके मुकाबले में शिंदे साहब को कम मिला होगा। इस दृष्टि से यह जो तीन वर्ष की लिमिट रखी गई है यह उचित नहीं है, केवल एक वर्ष होनी चाहिये। आपने स्वयं अपना जो भाषण दिया था और यह जो लां कमीशन की रिपोर्ट है बड़ी भारी ला कमीशन की, इन्होंने सारा वर्क आउट करके रख दिया है, एक साल, डेढ़ साल का पीरियड दिया है। आप तीनसाल का मांगते हैं। कौन सा ऐसा हिस्सा है जिस पर आप समझते हैं ज्यादा समय लगना चाहिये क्योंकि 4 (1) का नोटिस दिया, सर्वे के लिये 3–6 महीने–यह कमीशन की रिपोर्ट में दिया है– एतराज सुनने के लिये 2 महीने। सर्वे और एतराज का काम साथ साथ चल सकता है। तीन महीने में दोनों पूरे हो जाने चाहिये, कलेक्टर की रिपोर्ट आने के बाद डिटेल में प्लान बनाने के लिये दो महीने की आवश्यकता है। दूसरा धारा 6 के अन्दर घोषणा करने के लिये कुछ समय। 9 से साढ़े 12 महीने तक की अवधि है। मैं जानना चाहता हूं कि आयोग के मेंम्बरों को क्या कुछ ज्ञान नहीं था या उन्होने एवीडेन्स बराबर नहीं लिया या खाली पंखे के नीचे बैठकर रिपोर्ट दे दी।

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : चौरड़िया जी, 12 महीने से ज्यादा आप खुद मानते हैं। अब सवाल यह रह गया दो साल हों या तीन।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : श्रीमान्, आप देखेंगे कि 9 से साढ़े 12 महीने आयोग ने कहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : साढ़े 12 महीने तो एक साल से ज्यादा हो गया।

Now your argument could be whether it should be two years or three years.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : सभापति जी, अपनी बात मेरे मुंह में न डालिये आयोग ने जो रिपोर्ट दी मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। अब मैं यह कहता हूं कि आयोग ने साढ़े 12 महीने उदारतापूर्वक दिये। मैंने एक साल का जो एमेंडमेंट दिया है वह इसी आशय से दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि आयोग ने कौन सी जगह ऐसी बताई है जहां ज्यादा समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में मैंने जो संशोधन दिया है जनता के हित में और आपके स्वयं के हित में उससे न आपकी जमीन जावेगी और अगर 'पब्लिक परपज' के लिये ली भी जाय तो उसमें दस साल नहीं लगेंगे, तीन साल नहीं लगेंगे, एक साल का समय लगेगा, रेड टेपिज्म; लालफीताशाही में फंसेगा नहीं। इसी आशय से मैंने

[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया]

संशोधन दिया है । आशा है मंत्री महोदय इनको स्वीकार करने की कृपा करेंगे ।

The Question was proposed.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: Sir, we have given considerable thought to this and we thought that three years should be adequate but as far as the suggestion of the hon. Member is concerned, we shall forward his suggestion to the Committee which we propose to constitute and that Committee will go into the details of this provision. As far as clause 3 of the present Bill is concerned, I think the House should accept it as it is.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): The question is:

2. "That at page 2,—

(i) lines 6 to 13 be deleted;

(ii) in lines 20-21, for the words 'after the expiry of three years' the words 'after the expiry of one year' be substituted; and

(iii) lines 23-24 be deleted."

The *motion was negatived.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted. Clause 3 *was added to the Bill.*

Clause 4—*Validation of Certain Acquisitions*

SHRI V. M. CHORDIA: Sir, I move—

3. "That at pages 2 to 4, for the existing clause 4, the following be substituted, namely: —

'4. Notwithstanding anything contained in this Act, no declaration under section 6 of the principal Act in respect of any land which has been notified under sub-section (1) of section 4 of me principal Act, Deiore me commencement of the Land Acquisition (Amendment and Validation) Ordinance, 1967 shall be deemed to be invalid if all necessary proceedings have already been completed and possession of the land taken by the government"

हमारे मंत्री जी ने बहुत बढ़िया संशोधन किया 4(1) में । वह इस आशय से दिया बताते हैं कि हमारी मेडिकल कौंसिल का जो भवन हैं या भिलाई में जो कारखाना बनाया और जो मकान बनाये, वे हटा न दिये जायें । मैं भी इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं कि कहूं कि कानून की जरा सी गलती की वजह से इतनी बड़ी बड़ी सैकड़ों बिल्डिगें गिरा दी जायें। लेकिन इसकी आड़ में और भी गलतियां आपके कर्मचारियों ने की हैं उनको भी ढांकना चाहते हैं । अपने पाप को पुण्य में परिवर्तित कर लीजिये, मगर जो बाकी जमीन है जिसके बारे 1959 से घोषणा कर रखी है, उन लोगों को न दीन का रखा न दुनिया का, उसे रखना ठीक नहीं है। आपका भिलाई का प्राजेक्ट हटना नहीं चाहिये, मेडीकल इन्स्टीट्यूट नहीं हटना चाहिये, और जो बिल्डिगें बनी हुई हैं उनको हटना नहीं चाहिये, लेकिन जिस जमीन पर कुछ नहीं हुआ, लोगों से ले ली, उनको अनाज पैदा नहीं करने देते, कुंआ नहीं खोदने देते, उसे तो छोड़ देना चाहिये । अन्न संकट आप चिल्लाते हैं, और अन्न संकट साल्व करने के लिये जमीन पर कुंआ खोदने के लिये सिंचाई के साधन पैदा करने के लिये कोई आता है तो आप उसे अवसर देते नहीं । इस तरह की बातें इस सरकार को शोभा नहीं देती और इसी आशय से मैंने यह संशोधन दिया है ।

"Notwithstanding anything contained in this Act, no declaration under section 6 of the principal Act in respect of any land which has been notified under sub-section (1) of section 4 of the principal Act, before the commencement of the Land Acquisition (Amendment and Validation) Ordinance, 1967 shall

be deemed to be invalid if all necessary proceedings have already been completed and possession of the land taken by the Government."

जो जमीन सरकार ने अपने उपयोग में ली है उसके लिये तो ठीक है लेकिन जो खाली पड़ा है उसके लिये 'डाग इन दि मेन्जर पालिसी' अपना रखी है। आप कामन मेन के इन्टरेस्ट की बात कहते हैं, मैंने जो संशोधन दिया है उसको मान लेंगे तो मेडीकल इन्स्टीट्यूट तो नहीं गिरेगा, मगर साथ ही जनता के मकान भी नहीं गिरेंगे ।

The *question was proposed.*

SHRI ANNASAHIB SHINDE; Sir, I am not in a position to accept the amendment of the hon. Member but I must state that he has at least conceded my position that the lands the possession of which has been taken over should not be disturbed. I am glad that at least he recognises the necessity for this and concedes the important point on which the Bill stands. 1 am really thankful to him for this. As far as his other suggestion Is concerned I am not in a position to accept it because this is the heart of the Bill which I have brought before the House. The validation part is very Important and unless the previous acts are validated in respect of all lands including lands in respect of which notification under section 4 has been issued, 1 do not think the purpose of the Bill will be served. I am sorry I cannot accept this amendment.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): The question is:

3. "That at pages 2 to 4, for the existing clause 4, the following be substituted, namely: —

'4. Notwithstanding anything contained in this Act, no declaration under section 6 of the principal Act in respect of any land which has been notified under sub-section (1) of section 4 of the principal Act, before the commencement of the Land Acquisition (Amendment and Validation) Ordinance, 1947 shall be deemed to be invalid if all necessary proceedings have already been completed and possession of the land taken by the Government."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : The question is:

"That clause 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4 *was added to the Bill.*

Clause 5 *was added to the Bill.*

Clause 1, the *Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI ANNASAHIB SHINDE: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : उपसभाध्यक्ष महोदय जो बिल माननीय मंत्री जी रख रहे हैं वह अब तो पास हो रहा है लेकिन जिस कमेटी का इन्होंने रेफरेंस दिया उसके बारे में जानकारी चाहूंगा। इसको जरा खुलासा कर दें। 1958 ई० में जो रिपोर्ट आ गई तो उस पर अभी तक विचार क्यों नहीं किया । जिस काम को धक्के में डालना हो, पोल में डलाना हो उसके लिये यह है कि यह नई कमेटी बना कर देखेंगे। 1958 से 1967 हो गया, तो कमिशन की रिपोर्ट पर विचार करके क्यों नहीं काम किया गया। पहली बात।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M P. BHARGAVA): Which Report of which Commission?

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : वह मैं बताता हूं। The Report of the Law Commission of India, Tenth Report—Law of Acquisition and Requisitioning of Land, Government of India, Ministry of Law.

[श्री बिमलकुमार मन्दालालजी चौरडिया]

तो मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण दें । इस स्पष्टीकरण के साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आपके अपने फेज्ड प्रोग्राम के हिसाब से कितने दिनों में कमेटी बनेगी और कितने दिनों में रिपोर्ट प्राप्त करने की अपेक्षा कर के बिल पेश करने की क्षमता में हो जायेंगे । इस का भी खुलासा दे दें ।

SHRI ANNASAHIB SHINDE: As far as the recommendations of the Law Commission are concerned, Government has availed of those recommendations. I am afraid if all those recommendations are accepted, perhaps the hon. Member himself will object to the acceptance of those re-commendations.

SHRI V. M. CHORDIA: If there is reason.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: The point is the Law Commission itself has visualised the need for the Land Acquisition Act and most of the provisions, they say, are justified. The point is a political assessment has to be made. It is not only a technical point. Not only technical points have to be looked into, but taking into consideration the need to rehabilitate the poorer sections of the people, who are thrown out of their land and a number of such other problems, a political view of things has to be taken and that is why the Government have decided to constitute a Committee of Members of Parliament to go into this . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): In consultation with the State Governments.

SHRI ANNASAHIB SHINDE; As soon as we receive the replies from the State Governments, we shall constitute the Committee perhaps very soon . . .

SHRI V. M. CHORDIA: 'As soon as' means what?

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): I hope it is sooner than you fall.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: Being a subject falling in the Concurrent List, the consultation process will take some time. There will not be any delay on our part, as far as the Government of India is concerned. Our decision stands and the moment their recommendations are available, immediately in the next Session after the recommendations have been considered, we shall bring forward a Bill.

SHRI BHUPESH GUPTA: Only my request is this. It seems to me that the Government of India is functioning on an *ad hoc* basis. Therefore, 'very soon' should be defined. Now-a-days they say all things. Give us an idea of the time, because 'soon' dose not mean anything. As I said, they function on an *ad hoc* basis. One does not know when they are falling.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

THE MINERAL PRODUCTS (ADDITIONAL DUTIES OF EXCISE AND CUSTOMS) AMENDMENT BILL, 1967

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Mineral Products (Additional Duties of Excise and Customs) Act, 1958, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The Bill seeks to replace the Ordinance promulgated by the President on the 15th December, 1966. The circumstances which led to the issue of this Ordinance have already been explained in the statement circulated